केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

जलांश

खंड 6 अंक 5 दिसंबर- 2023

संदेश

श्री कुशविंदर वोहरा
अध्यक्ष, के ज आ

हमने इस महीने की शुरुआत सतर्कता जागरूकता सप्ताह के साथ की, जो भारत में सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस वर्ष का विषय था " भ्रष्टाचार का विरोध करें,राष्ट्र के प्रति समर्पित"। के.ज.आ. के अधिकारियों को सतर्कता सिद्धांतों को बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। इसके अतिरिक्त, के.ज.आ. के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ने पूरे सप्ताह जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया।

इस महीने के दौरान 01.11.2023 से 08.11.2023 तक अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी आयोग (आईसीआईडी) की 25वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और 74वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (आईईसी)का आयोजन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। के.ज.आ. में स्थित आईएनसीआईडी ने आईसीआईडी और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आईसीआईडी कांग्रेस का उद्घाटन विशाखापत्तनम में भारत सरकार के माननीय जल शक्ति मंत्री और आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में 40 देशों के 350 विदेशी प्रतिनिधियों सहित दुनिया भर से लगभग 1300 विशेषज्ञ, शोधकर्ता और पेशेवर एक साथ आए। इसका श्रेय आयोजन में शामिल के.ज.आ. अधिकारियों को जाता है।

हमें 15.11.2023 को घाना सरकार के संचार और डिजिटलीकरण उप मंत्री माननीय अमा पोमा बोटेंग के नेतृत्व में घाना के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करने का सम्मान मिला। उन्होंने हमारे हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन नेटवर्क, बाढ़ पूर्वानुमान तंत्र और बांध सुरक्षा गतिविधियों को समझने के लिए के.ज.आ. का दौरा किया। इन पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गईं; और हमने उन्हें जल क्षेत्र से संबंधित सभी मुद्दों में उनकी क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने में अपने समर्थन का आश्वासन दिया। नवंबर 2023 के दौरान के.ज.आ. द्वारा एक और मील का पत्थर हासिल किया गया जब 29.11.2023 को मेरे द्वारा हुई बैठक में यूपी और उत्तराखंड के बीच यमुना जल (ओखला तक) के बंटवारे पर सहमति बनी।

मैंने 2023 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में व्यापक बाढ़ के मद्देनजर संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन के लिए गठित समिति की पहली बैठक भी की। महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें हाइड्रोलॉजिकल नेटवर्क, वर्षा विश्लेषण, डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) निर्माण और बांध सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा के लिए एक मास्टर डेटाशीट तैयार करना शामिल है।

इसके अलावा, हथिनीकुंड और ओखला बैराज के बीच पहुंच के लिए यमुना नदी के संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन समिति की दूसरी बैठक आयोजित की गई। सभी समस्याओं को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए एक व्यापक अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके अलावा, विचार-विमर्श के बाद समिति की अंतरिम रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

के.ज.आ. ने बीआईएस की मानकीकरण गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। डब्ल्यूआरडीसी, बीआईएस के अध्यक्ष के रूप में, मैंने जल क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में तीन कोड को मंजूरी दी।

आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। के.ज.आ. 2024 के दौरान भी नई उपलब्धियां हासिल करती रहे।

विषयसूची

विदेशी प्रतिनिधिमंडल
- घाना से प्रतिनिधिमंडल
- अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग (आईसीआईडी) की 25वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और 74वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (आईईसी)

एनडीएसए और डीआरआईपी
- डीआरआईपी चरण II और III के लिए इंजीनियरिंग और प्रबंधन परामर्श के संबंध में समीक्षा समिति की दूसरी बैठक

परियोजना के संबंध में बैठक
- पुनात्सांगछू-I एचईपी (6 X200 मेगावाट), भूटान
- रेणुकाजी बांध परियोजना, हिमाचल प्रदेश
- किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाएँ
- लखवार परियोजना बहुद्देशीय परियोजना
- उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना, झारखंड
- सप्तकोसी बहुद्देशीय परियोजना
- द्वितीय रावी व्यास लिंक, पंजाब

प्रशिक्षण की कार्यशाला
- विश्व बैंक द्वारा वेबिनार का आयोजन

दौरा/निरीक्षण
- हीराकुंड बांध, ओडिशा
- लोक लेखा समिति (2023-24) का डुआर्स (सिलीगुड़ी) और कोलकाता का अध्ययन दौरा

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

i. बाढ़ और संबंधित मुद्दे
- 2023 में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्य में व्यापक बाढ़ के मद्देनजर संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन समिति की पहली बैठक
- पश्चिम बंगाल में गंगा-पद्मा नदी प्रणाली द्वारा उत्पन्न कटाव
- "बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन" पर अध्ययन रिपोर्ट
- देश में बाढ़ की स्थिति -नवंबर 2023
- हथनीकुंड और ओखला बैराज के बीच पहुंच के लिए यमुना नदी के संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन के लिए गठित समिति की दूसरी बैठक

ii. अंतरराज्यीय मामले
- ओखला तक यमुना जल में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के हिस्से के पुनः आवंटन के मुद्दे पर समिति की तीसरी बैठक
- रिहंद जलाशय पर जेओसी की 35वीं बैठक

iii. अन्य गतिविधियाँ
- डब्ल्यूएआरआईएमएस पोर्टल के बीएसआर की प्रगति का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक
- बीआईएस कोड को अंतिम रूप देना/अपनाना और नई अनुभागीय समिति का गठन

iv. जलाशय निगरानी

v. हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें/जल निकाय

विदेशी प्रतिनिधिमंडल

घाना से प्रतिनिधिमंडल

घाना सरकार के संचार और डिजिटलीकरण उप मंत्री माननीय अमा पोमा बोटेंग के नेतृत्व में घाना से एक प्रतिनिधिमंडल और आंतरिक मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संगठन, राष्ट्रीय संचार प्राधिकरण, प्रारंभिक चेतावनी और प्रतिक्रिया तंत्र के समन्वय के लिए राष्ट्रीय केंद्र, घाना मौसम विज्ञान एजेंसी आदि के अन्य टीम के सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अधिकारियों के साथ 15.11.2023 को केंद्रीय जल आयोग का दौरा किया और केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा से मुलाकात की।

घाना प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का उद्देश्य के.ज.आ. के हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन नेटवर्क, बाढ़ पूर्वानुमान तंत्र के साथ-साथ देश में बांध सुरक्षा गतिविधि को समझना था।

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और देश में जल संसाधन क्षेत्र में के.ज.आ. की भूमिका, के.ज.आ. द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों, के.ज.आ. के पास उपलब्ध प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे, भविष्य के लिए के.ज.आ. के दृष्टिकोण आदि के बारे में जानकारी दी।

के.ज.आ. के अधिकारियों द्वारा के.ज.आ. के अवलोकन, हाइड्रो-मेट्रोलॉजिकल अवलोकन नेटवर्क, बाढ़ पूर्वानुमान और बांध सुरक्षा पर प्रस्तुतियां दी गईं।

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने इन गतिविधियों को पूरा करने के लिए देश में स्थापित संस्थागत तंत्र के बारे में भी विस्तार से बताया। घाना प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत बातचीत की गई। घाना सरकार के संचार और डिजिटलीकरण उप मंत्री ने के.ज.आ. द्वारा समेकित तरीके से संभाले जाने वाले जल क्षेत्र से संबंधित संस्थागत तंत्र और तकनीकी मामलों की सराहना की। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदान की गई जानकारी उनकी कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए बहुत उपयोगी है।

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने घाना को उनकी क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ जल क्षेत्र से संबंधित अन्य मुद्दों पर परामर्श प्रदान करने का आश्वासन दिया और उनसे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से मुद्दे को उठाने का अनुरोध किया।

अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग (आईसीआईडी) की 25वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और 74वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (आईईसी)

अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी आयोग (आईसीआईडी) एक प्रमुख वैज्ञानिक, तकनीकी और पेशेवर गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो टिकाऊ कृषि जल प्रबंधन को बढ़ावा देने और प्राप्त करने के लिए सिंचाई, जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने के लिए समर्पित है। एक ज्ञान-साझाकरण मंच के रूप में, आईसीआईडी कृषि जल प्रबंधन प्रथाओं की स्थिति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें वर्षा आधारित कृषि, पूरक सिंचाई, अपर्याप्त सिंचाई और पूर्ण सिंचाई जैसे विभिन्न तरीकों को शामिल किया गया है। इसकी मुख्य गतिविधियाँ कृषि भूमि के जल निकासी और बाढ़ और सूखे जैसी चरम जलवायु घटनाओं के प्रबंधन तक फैली हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (आईईसी) आईसीआईडी के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह सदस्य राष्ट्रीय समितियों, पदाधिकारियों या प्रबंधन बोर्ड द्वारा शुरू की गई या प्रायोजित नीति के मामलों पर विचार करता है। आईईसी, जिसमें प्रत्येक राष्ट्रीय समिति के पदाधिकारी और प्रतिनिधि शामिल होते हैं, कार्यकारी, प्रशासनिक कार्यों और वित्तीय देनदारियों पर निर्णायक निर्णय लेने के लिए सालाना बैठक करते हैं।

आई सी आई डी मुख्य रूप से प्रतिनिधि राष्ट्रीय समितियों (एनसी) के माध्यम से संचालित होती है, जिसमें सिंचाई और जल निकासी पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आईएनसीआईडी) भारत की प्रतिनिधि है। आई एन सीआईडी की स्थापना आईसीआईडी के साथ घनिष्ठ बातचीत के माध्यम से सिंचाई और जल निकासी में सुधार के लिए भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। आईसीआईडी कृषि जल के प्रबंधन, जल कूटनीति का उपयोग करने, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने और राष्ट्रों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करने में विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई एन सीआईडी अपने विविध प्रकार के विशेषज्ञों के माध्यम से भारत के कृषि विकास, सिंचाई के बुनियादी ढांचे, स्थिरता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और ज्ञान के आदान-प्रदान का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आई एन सीआईडी, केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) के अध्यक्ष और सीई (ईएमओ) के नेतृत्व में, के.ज.आ. इसके सदस्य सचिव के रूप में, और रिमोट सेंसिंग निदेशालय, के.ज.आ., आईएनसीआईडी सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

आईसीआईडी के साथ राष्ट्रीय इंटरफेस के रूप में कार्यरत आईएनसीआईडी ने 1-8 नवंबर, 2023 तक आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम (विजाग) में आईसीआईडी की 25वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और 74वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (आईईसी) बैठक का आयोजन किया। यह आयोजन पूरी तरह से केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) के अधिकारियों के योगदान से एक आंतरिक प्रयास था, जो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार और आईसीआईडी के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में वैश्विक स्तर पर 1300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 40 देशों के लगभग 350 विदेशी प्रतिनिधि शामिल थे।

25वीं आईसीआईडी कांग्रेस, जिसका विषय 'कृषि में पानी की कमी से निपटना' था, का उद्घाटन भारत सरकार के माननीय जलशक्ति मंत्री और आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। भव्य उद्घाटन समारोह में आंध्र प्रदेश के जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा, और उद्योग, बुनियादी ढांचे, निवेश और वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रियों के साथ-साथ आईसीआईडी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव सहित प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। के.ज.आ. और आईएनसीआईडी के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा ने खाद्य और पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षा के लिए स्थायी जल प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया। माननीय मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के सामने जल क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। माननीय मंत्री ने जलवायु

परिवर्तन के सामने जल क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। माननीय मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के सामने जल क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। माननीय मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के सामने जल क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। माननीय मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश राज्य में जल संसाधन विकास और प्रबंधन के लिए आवश्यक विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया। आईसीआईडी के अध्यक्ष ने सिंचाई, जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में स्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में आईसीआईडी की अग्रणी भूमिका से अवगत कराया।

प्रतिष्ठित आईसीआईडी कांग्रेस; जल संसाधन प्रबंधन, सिंचाई और जल निकासी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए समर्पित 40 देशों के 350 विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 1300 विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों की एक वैश्विक मंडली को एक साथ लाया।

25वीं आईसीआईडी कांग्रेस का विषय था 'कृषि में पानी की कमी से निपटना', जिसमें दो प्रश्नों के समाधान के लिए विभिन्न सत्र आयोजित किए गए:

प्रश्न 64: सिंचित कृषि के लिए कौन से वैकल्पिक जल संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है?

उप-प्रश्न 64.1: सिंचाई जल के पारंपरिक स्रोतों का विकास और सुदृढ़ीकरण (6 सत्र)

उप-प्रश्न 64.2: जल के गैर-पारंपरिक स्रोतों का दोहन (1 सत्र)

उप-प्रश्न 64.3: कृषि में पानी की कमी को दूर करने में किसानों का सशक्तिकरण (प्रथम सत्र)

प्रश्न 65: कौन सी ऑन-फ़ार्म तकनीकें जल उत्पादकता बढ़ा सकती हैं?

उप-प्रश्न 65.1: मौजूदा सुविधाओं के प्रबंधन में सुधार (2 सत्र)

उप-प्रश्न 65.2: उन्नत कृषि पद्धतियाँ और अनुसंधान/नवाचार (1 सत्र)

उप-प्रश्न 65.3: सिंचाई जल का कुशल अनुप्रयोग (7 सत्र)

कांग्रेस के दौरान, 2-4 नवंबर, 2023 तक विभिन्न विभागों, एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 15 साइड इवेंट भी आयोजित किए गए, जिनमें ये आईडब्ल्यूएमआई-डब्ल्यूआरसी, आईएनसीआईडी और भारत एनपीआईएम सत्र, एफएओ-वासाग,एफएओ,एमएसएसआरएफ-नॉर्वे,आईएनसीआईडी-महिलाएं और पानी, आईडब्ल्यूएमआई-इंडिया, आईजीएस, एएफआईडी, आईईडब्ल्यूपी जीआईज़ सत्र, इकार्डा, एफएओ-जेआईसीए, सीएनसीआईडी (वर्ल्ड इरिगेशन फोरम 4 पेपर्स), आईएनसीआईडी और आईडब्ल्यूआरएस, और आईडब्ल्यूएमआई-सौर सिंचाई कार्यक्रम भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, के.ज.आ. के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक आई एन सीआईडी कांग्रेस विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें दो सत्रों में "भारत में जल क्षेत्र की चुनौतियों के स्थायी समाधान" पर ध्यान केंद्रित किया गया। एक सत्र में केंद्र सरकार की संस्थाओं जैसे के.ज.आ., सीजीडब्ल्यूबी, एनडब्ल्यूए, पुणे और डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर की आर एंड डी गतिविधियों की प्रस्तुतियाँ शामिल थीं। दूसरे सत्र में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसी राज्य सरकारों के प्रस्तुतीकरण शामिल थे।

5 नवंबर,2023 को 300 स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए अराकु वैली और बोर्रा गुफाओं का एक तकनीकी दौरा आयोजित किया गया था। पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए कंबलाकोंडा इको पार्क, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, सिम्हाचलम मंदिर, ऋषिकोंडा समुद्र तट आदि के लिए कई स्थानीय अध्ययन पर्यटन और भ्रमण यात्राएं भी आयोजित की गईं।

कांग्रेस और आईईसी को 8-दिवसीय कार्यक्रम के रूप में एक साथ आयोजित किया गया था, जिसमें 2-4 नवंबर, 2023 तक कांग्रेस थी, इसके बाद 5-8 नवंबर तक आईईसी बैठकें हुईं, जिसमें आईसीआईडी के विभिन्न कार्य समूहों और समितियों को शामिल किया गया।

के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा ने आईसीआईडी की 74वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (आईईसी) बैठक के दौरान सी-कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की। श्री वोहरा ने 4 नवंबर, 2023 को संपन्न हुई 25वीं आईसीआईडी कांग्रेस के दौरान भागीदारी का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया और कांग्रेस के वित्तीय और तकनीकी पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी। आईई डब्ल्यू पी, जीआईजेड द्वारा आयोजित एक युवा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी 5 नवंबर, 2023 को आयोजित किया गया था। आईई डब्ल्यू पी, जीआईजेड द्वारा आयोजित एक युवा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी 5 नवंबर, 2023 को आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रासंगिक विषयों को कवर करते हुए, 5-8 नवंबर तक लगभग 20 कार्य समूह की बैठकें आयोजित की गईं। अन्य आईईसी बैठकों में पीसीटीए, पीएससीओ, आईईसी शामिल थे।

आखिरी दिन, 8 नवंबर को आईईसी बैठक हुई और समापन समारोह के साथ समाप्त हुआ।

एनडीएसए और डीआरआईपी

डीआरआईपी चरण II और III के लिए इंजीनियरिंग और प्रबंधन परामर्श के संबंध में समीक्षा समिति की दूसरी बैठक

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 17.11.2023 को सदस्य (डी एंड आर) के कक्ष में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण II और III के लिए इंजीनियरिंग और प्रबंधन परामर्श के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक सलाहकार कर्मियों की सक्रियता के संबंध में सलाहकार द्वारा प्रस्तुत सीवी की जांच करने और अनुमोदन के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की सिफारिश करने के लिए की गई थी।

परियोजना के संबंध में बैठक

पुनात्सांगछू-I एचईपी (6 X200 मेगावाट), भूटान

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 03.11.2023 को समिति कक्ष, के.ज.आ. में प्रगति समीक्षा के संबंध में पुनात्सांगछू-I एचईपी (6 X 200 मेगावाट), भूटान की 32वीं तकनीकी समन्वय समिति की बैठक में भाग लिया। श्री एस.डी. शर्मा, मुख्य अभियंता, डिज़ाइन (ई एवं एनई), श्री एस.के. शर्मा, निदेशक, बीसीडी (ईएंडएनई) भी बैठक में शामिल हुए।

रेणुकाजी बांध परियोजना, हिमाचल प्रदेश

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 06.11.2023 को सदस्य (डी एंड आर) के कक्ष में रेणुकाजी बांध परियोजना के लिए भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों के पैनल, के.ज.आ., सीएसएमआरएस, जीएसआई और एचपीपीसीएल के अधिकारियों के साथ रेणुकाजी बांध परियोजना, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक निविदा चरण को आगे बढ़ाने के लिए रेणुकाजी बांध स्थल पर चल रहे जांच कार्य की स्थिति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई थी।

किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजना (एचईपी)

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 20.11.2023 को समिति कक्ष, के.ज.आ. में के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में किशनगंगा और रतले एचईपी से संबंधित आईडब्ल्यूटी मुद्दों के लिए 'तकनीकी उप-समिति' की 12वीं बैठक में भाग लिया। श्री मनोज तिवारी, सीई, एचएसओ, श्री विवेक त्रिपाठी, सीई डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) के साथ-साथ के.ज.आ. और एनएचपीसी के अन्य अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक का एजेंडा तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा डेटा अनुरोध पर चर्चा करना था।

लखवार बहुद्देशीय परियोजना

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 22.11.2023 को सदस्य (डी एंड आर) के कक्ष में लखवार बहुउद्देश्यीय परियोजना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए के.ज.आ., यूजेवीएनएल, जीएसआई, भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों के समूह (जीजीई) और एल एंड टी के अधिकारियों के बीच हाइब्रिड बैठक की अध्यक्षता की।

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना, झारखंड

सचिव, डब्ल्यूआर, आरडी एवं जीआर की अध्यक्षता में 29.11.2023 को एक बैठक में उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। एफएम विंग, डीओडब्ल्यूआर, के.ज.आ. मुख्यालय और डब्ल्यूएपीसीओएस के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें दिसंबर के तीसरे सप्ताह में CWC और WAPCOS द्वारा 10 निर्मित गेटों का संयुक्त निरीक्षण शामिल था, जिसमें झारखंड सरकार से R&R मुद्दों को संबोधित करने और 15 दिनों के भीतर भुगतान के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने, 8वें RCE प्रावधानों के अनुरूप RMC, झारखंड में बिजली के पोल शिफ्टिंग मामले को हल करने का आग्रह किया गया था तथा राज्य सरकार से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करने के लिए डीओ लेटर के माध्यम से मुख्य सचिव, झारखंड से अनुरोध किया गया है।

सप्तकोसी बहुद्देशीय परियोजना

सप्त कोसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं (एसकेएमपी) और सन कोसी कमला डायवर्जन बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं (एसकेडीएमपी) के लिए किए जाने वाले ड्रिलिंग और ड्रिफ्टिंग मानदंडों पर चर्चा के लिए के.ज.आ., जीएसआई और सीएसएमआरएस अधिकारियों के बीच सीई, डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) की अध्यक्षता में 08.11.2023 को के.ज.आ. में बैठक बुलाई गई थी।

द्वितीय रावी व्यास लिंक, पंजाब

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने डब्ल्यूआरडी, जीओपी द्वारा प्रस्तुत दूसरी रावी ब्यास लिंक परियोजना की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) की प्रगति पर चर्चा करने के लिए 28.11.2023 को एक बैठक की। बैठक में डब्ल्यूआरडी, पंजाब सरकार (जीओपी), केंद्रीय जल आयोग और अन्य संबंधित संगठनों के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, के.ज.आ. के अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि के.ज.आ. के डिजाइन विंग की एक टीम एक सप्ताह के भीतर बैराज के मापदंडों को अंतिम रूप देने के लिए साइट का दौरा कर सकती है। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर पीएफआर के डिजाइन और लागत पहलू, सफलता दर और लाभ-लागत अनुपात को अंतिम रूप देने के लिए के.ज.आ. के संबंधित विशेष निदेशालयों द्वारा डब्ल्यूआरडी, जीओपी के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

प्रशिक्षण की कार्यशाला

विश्व बैंक द्वारा वेबिनार का आयोजन

ऑस्ट्रेलियाई जल साझेदारी के सहयोग से विश्व बैंक द्वारा आयोजित पहला वेबिनार 28.11.2023 को आयोजित किया गया, जो बांधों के संचालन और प्रबंधन पर केंद्रित था। यह विश्व बैंक द्वारा बांध सुरक्षा और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों पर ज्ञान विनिमय वेबिनार की श्रृंखला का हिस्सा है। इन वेबिनार का उद्देश्य भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायियों/पेशेवरों के बीच ज्ञान साझा करना और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखना है। यह डीआरआईपी कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए एक उत्कृष्ट शिक्षण मंच और पिछले दस वर्षों से प्राप्त अपने अनुभव को व्यापक दर्शकों के साथ साझा करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

दौरा/निरीक्षण

हीराकुंड बांध, ओडिशा

संयुक्त सचिव (पीपी एंड आरडी), डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, मुख्य अभियंता, डीएसओ, के.ज.आ. और परियोजना निदेशक, डीआरआईपी और एसजेसी, पीआर विंग, एमओजेएस ने 23 नवंबर, 2023 को हीराकुंड बांध का दौरा किया। यात्रा के दौरान, अधिकारी ने चल रहे बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, चरण- II और III के तहत हीराकुंड बांध (अतिरिक्त स्पिलवे कार्य) के व्यापक पुनर्वास के संबंध में परियोजना अधिकारियों के साथ चर्चा की।

लोक लेखा समिति (2023-24) का डुआर्स (सिलीगुड़ी) और कोलकाता का अध्ययन दौरा

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 25 से 26 नवंबर 2023 तक डुआर्स (सिलीगुड़ी) और कोलकाता में लोक लेखा समिति (2023-24) की अध्ययन यात्रा में भाग लिया। 25.11.2023 को सिलीगुड़ी में जलशक्ति मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार, केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, ब्रह्मपुत्र बोर्ड और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ "सीएंडएजी रिपोर्ट संख्या 10 से 2017 के आधार पर बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ पूर्वानुमान के लिए योजनाओं पर प्रदर्शन ऑडिट" विषय पर एक अनौपचारिक चर्चा की गई।

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

बाढ़ और संबंधित मुद्दे

2023 में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्य में व्यापक बाढ़ के मद्देनजर संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन समिति की पहली बैठक

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 2023 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्य में व्यापक बाढ़ के मद्देनजर संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन के लिए गठित समिति की पहली बैठक 21.11.2023 को की।

बैठक में पंजाब सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, बीबीएमबी, सीडब्ल्यूपीआरएस, आईएमडी, एनआरएससी, एनडब्ल्यूआईसी और सीडब्ल्यूसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

समिति के अध्यक्ष ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में उन विभिन्न कारकों पर प्रकाश डाला जो इन क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बन सकते हैं और समिति द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण दिया। आईएमडी, बीबीएमबी, एचपी, पंजाब और यूके द्वारा विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुतियां दी गईं। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे विभिन्न संबंधित एजेंसियों के हाइड्रोलॉजिकल नेटवर्क के लिए मास्टर डेटाशीट तैयार करना, प्रमुख बाढ़ की घटनाओं का वर्षा विश्लेषण, क्रॉस सेक्शन सर्वेक्षण सहित डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) की तैयारी, भाखड़ा और पोंग बांध के नियम वक्र की समीक्षा, तटबंध विवरण साझा करना/ क्रॉसड्रेनेज विवरण, बीबीएमबी की मौजूदा निर्णय समर्थन प्रणाली की समीक्षा आदि।

इसके अलावा, अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने संबंधित राज्यों/एजेंसियों से मौजूदा गेट संचालन तंत्र, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए मौजूदा बाढ़ मैदान क्षेत्र के प्रावधानों और मौजूदा बाढ़ प्रबंधन अभ्यास पर भी जानकारी मांगी।

पश्चिम बंगाल में गंगा-पद्मा नदी प्रणाली द्वारा उत्पन्न कटाव

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 24.11.2023 को पश्चिम बंगाल में गंगा-पद्म नदी प्रणाली द्वारा उत्पन्न कटाव के खतरे से निपटने के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करने के लिए एक संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन करने के लिए गठित समिति की तीसरी बैठक की।

बैठक में जल शक्ति मंत्रालय, सीडब्ल्यूसी, जीएफसीसी, सीडब्ल्यूपीआरएस, फरक्का बैराज परियोजना, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड राज्य, एनआरएससी, आईडब्ल्यूएआई के अधिकारी और सलाहकार मेसर्स ट्रैक्टेबल के विशेषज्ञ शामिल हुए।

बैठक के दौरान विभिन्न स्रोतों से डेटा संग्रह सहित अध्ययन की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रारंभिक मॉडल सेटअप पर चर्चा की गई। सलाहकार को अब तक किए गए अध्ययन को सुझावों, यदि कोई हो, के लिए सीडब्ल्यूपीआरएस और सीडब्ल्यूसी के साथ साझा करने का निर्देश दिया गया ताकि अध्ययन में तेजी लाई जा सके। वर्तमान संवेदनशील पहुंच और भविष्य के कटाव पैटर्न का अध्ययन करने के लिए आगे सुझाव दिए गए। अध्ययन की लक्ष्य पूर्णता अवधि को भी अंतिम रूप दिया गया।

"बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन" पर अध्ययन रिपोर्ट

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने बिहार राज्य में" फरक्का बैराज के कारण गंगा और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन हेतु मेसर्स आरएमएसआई प्राइवेट लिमिटेड की अंतिम अध्ययन रिपोर्ट के संबंध में सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) द्वारा 23.11.2023 को सचिव कक्ष में ली गई बैठक में भाग लिया। बैठक में प्रस्तुत इस अध्ययन रिपोर्ट के अंतिम परिणाम पर सीडब्ल्यूसी द्वारा एक प्रस्तुति दी

गई। प्रस्तुतिकरण में मुख्य अभियंता (एचएसओ) श्री मनोज तिवारी भी शामिल हुए।

देश में बाढ़ की स्थिति-नवंबर,2023

ब्रह्मपुत्र और बराक और झेलम बेसिन में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 01.05.2023 को शुरू हुई। 1 मई से 30 नवंबर 2023 की अवधि के दौरान, कुल 6306 (4566 स्तर+1740 प्रवाह) बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए, और 5934 (4336 स्तर+1598 प्रवाह) पूर्वानुमान 94.10% सटीकता के साथ अनुमेय सीमा के भीतर थे। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से माह नवम्बर में एक रेड बुलेटिन (अत्यधिक बाढ़ की स्थिति के लिए) एवं 03 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किये गये।

01.05.2023 से 31.10.2023 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

चरम बाढ़ की स्थिति

05 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

क्र.सं.	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन	अवधि	
					से	तक
1	एनसीटी दिल्ली	उत्तरी दिल्ली	यमुना	दिल्ली रेलवेब्रिज	12/07/2023	15/07/2023
2	उत्तर प्रदेश	बदायूँ	गंगा	कछलाब्रिज	14/07/2023 16/07/2023 29/07/2023 18/08/2023	15/07/2023 22/07/2023 01/08/2023 20/08/2023
3	असम	शिवसागर	दिखो	शिवसागर	17/07/2023 11/08/2023	17/07/2023 12/08/2023
4	तेलंगाना	कुमुराम भीम	वर्धा	सिरपुर नगर	24/07/2023 29/07/2023	24/07/2023 29/07/2023
5	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	तीस्ता	मेल्ली	04/10/2023	04/10/2023

55 बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

गंभीर बाढ़ की स्थिति

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड,महाराष्ट्र, राजस्थान, और गुजरात में 76 एफएफ स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, दादरा और नगर हवेली, ओड़िशा, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 65 निगरानी स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, ओडिशा ,मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडू में 45 एफएफ स्टेशन पर बाढ़ की स्थिति सामान्य से ऊपर देखी गई।

सीमा-रेखा से अधिक प्रवाह वाले जलाशय

आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 77 जलाशयों में उनकी सीमा से अधिक प्राप्त हुआ।

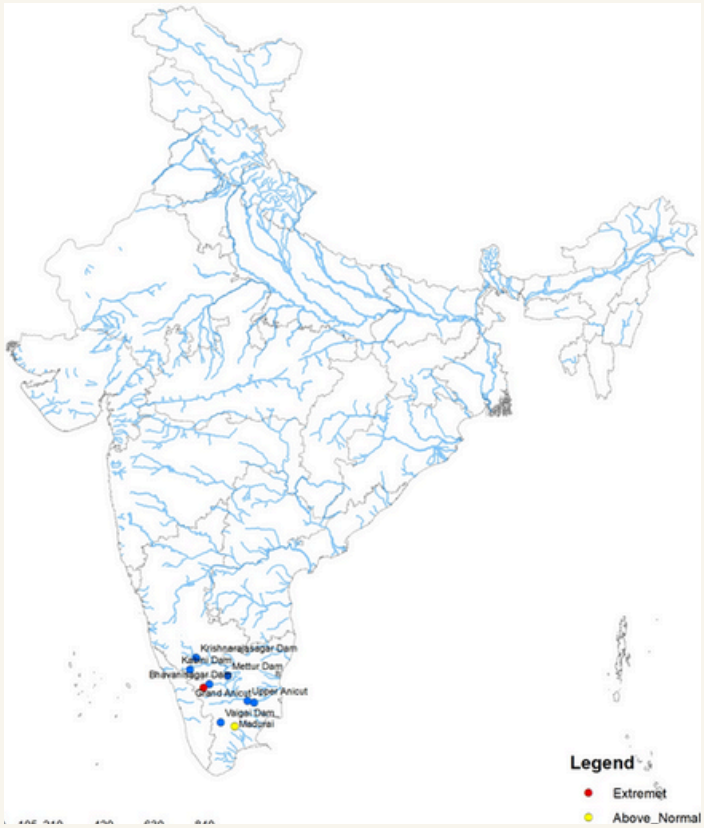

हथनीकुंड और ओखला बैराज के बीच पहुंच के लिए यमुना नदी के संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन के लिए गठित समिति की दूसरी बैठक

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 13.11.2023 को हथिनीकुंड और ओखला बैराज के बीच पहुंच के लिए यमुना नदी के संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन के लिए गठित समिति की दूसरी बैठक की। बैठक में एनसीटी दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सीडब्ल्यूपीआरएस, आईएमडी, डीडीए, एनआरएससी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और सीडब्ल्यूसी के अधिकारी शामिल हुए।

लंबित जानकारी की स्थिति जैसे पुलों की ड्राइंग, डीटीएम, बैराजों की परिचालन अनुसूची आदि सहित संरचनाओं की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की गई। जल निकासी क्षमता, तूफान वापसी अवधि के अनुसरण में जल निकासी डिजाइन आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सभी समस्याओं को समग्र रूप से समझने के लिए संपूर्ण पहुंच का व्यापक अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी से यथाशीघ्र अपेक्षित शेष डेटा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि मॉडलिंग अध्ययन किया जा सके।

2. अंतरराज्यीय मामले

ओखला तक यमुना जल में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के हिस्से के पुनः आवंटन के मुद्दे पर समिति की तीसरी बैठक

श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग और भारत सरकार के पदेन सचिव ने 29.11.2023 को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच 1994 के समझौता ज्ञापन के अनुसार ओखला तक यमुना जल में पूर्व उत्तर प्रदेश के हिस्से के पुनर्वितरण के मुद्दे पर समिति की तीसरी बैठक की।

बैठक में डी ओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, केंद्रीय जल आयोग और ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त एमओयू में बताए गए आवंटन और अन्य प्रासंगिक कारकों के अनुसार मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष ने दोनों राज्यों के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया और अंततः दोनों राज्यों के बीच इस मामले में एक सौहार्दपूर्ण समझौता हुआ।

रिहंद जलाशय पर जेओसी की 35वीं बैठक

श्री नवीन कुमार, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी) ने रिहंद जलाशय पर 35वीं संयुक्त संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जो 30.11.2023 को सेवा भवन में आयोजित की गई थी। बैठक में सीई, बीपीएमओ और केंद्रीय जल आयोग, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीजेवीएनएल) और उत्तर प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (यूपीएसएलडीसी) के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। समिति ने 2023-24 के लिए यूपीजेवीएनएल द्वारा प्रस्तावित रिहंद हाइड्रोपावर स्टेशन से रिलीज के साथ-साथ बिहार की जल मांग अनुसूची और बिजली उत्पादन योजना पर विचार-विमर्श किया। समिति के सदस्यों द्वारा दिसम्बर 2023 से जून 2024 तक जल छोड़े जाने के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया।

3. अन्य गतिविधियाँ

डब्ल्यूएआरआईएमएस पोर्टल के बीएसआर की प्रगति का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक

श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी द्वारा सीडब्ल्यूसी (मुख्यालय), नई दिल्ली में 30.11.2023 को WARIMS पोर्टल के बीएसआर की प्रगति का आकलन करने के लिए 5वीं समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में एमई/एसएमएन, समन्वय निदेशालयों के निदेशक और संबंधित मुख्य अभियंताओं ने भाग लिया। बैठक में बीएसआर की स्थिति और WARIMS में प्रगति/मुद्दों पर चर्चा की गई।

बीआईएस कोड को अंतिम रूप देना/अपनाना और नई अनुभागीय समिति का गठन

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 30.11.2023 को बीआईएस कोड को अंतिम रूप देने/ अपनाने और नई अनुभागीय समिति के गठन पर एक बैठक की।

बैठक में बीआईएस की अनुभागीय समितियों में सीडब्ल्यूसी सदस्यों के साथ सदस्य डी एंड आर ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, 04 आईएस कोड पर विचार-विमर्श किया गया और इनमें से 03 आईएस कोड को अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी और अध्यक्ष, डब्ल्यूआरडीसी, बीआईएस द्वारा अनुमोदित किया गया और मुद्रण के लिए अपनाया गया। अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने जलाशयों से वाष्पीकरण के नुकसान को कम करने के लिए

बीआईएस कोड की समीक्षा करने का निर्देश दिया, विशेष रूप से कवर किए जा सकने वाले जलाशय के क्षेत्र पर मार्गदर्शन के संबंध में दिशानिर्देश दिए। इसके अलावा, अध्यक्ष ने कार्यक्षेत्र और संरचना के साथ 04 नई अनुभागीय समितियों के गठन को मंजूरी दी और सीडब्ल्यूसी से सदस्यों को नामित किया।

4. जलाशय निगरानी

जलाशय निगरानी

सीडब्ल्यूसी साप्ताहिक आधार पर देश के 150 जलाशयों की लाइव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रही है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रही है। इन जलाशयों में से 20 जलाशय पनबिजली परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 35.299 बीसीएम है। इन 150 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 178.784 बीसीएम है, जो देश में सृजित अनुमानित भंडारण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 69.35% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 31.11.2023 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण 116.571 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 65% है। हालाँकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण 148.612 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत संग्रहण 127.747बीसीएम था। इस प्रकार, 31.11.2023 बुलेटिन के अनुसार 150 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण पिछले वर्ष की इसी

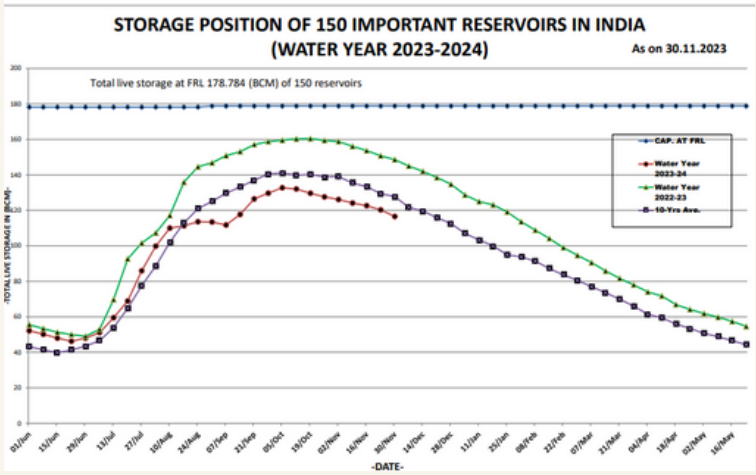

अवधि के संग्रहण का 78% और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 91% है।

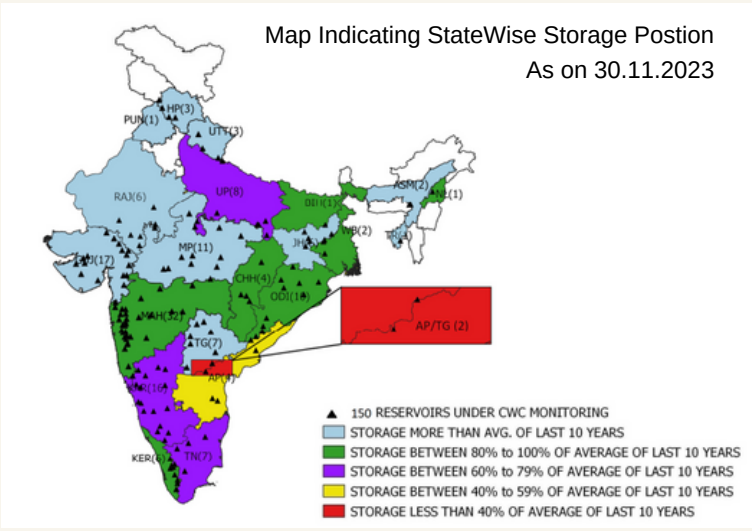

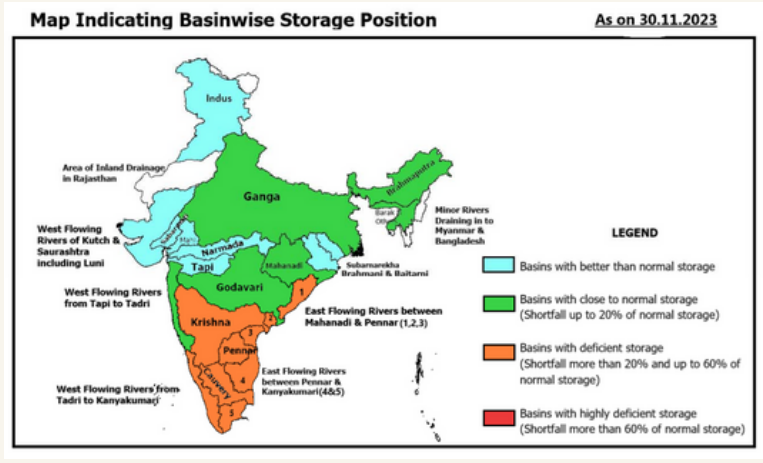

5. हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें/जल निकाय

हिमानीकृत बेसिन की अधिक ऊंचाई वाले विस्तार पर हिमानी झीलें होना सामान्य हिमानी झीलें हैं। इनका निर्माण तब होता है जब हिमानी बर्फ या मोराइन या प्राकृतिक अवसाद पानी को रोकते हैं। ऐसी झीलों की कई किस्में हैं, जिनमें ग्लेशियर की सतह पर पिघले पानी के तालाबों से लेकर मुख्य घाटी में ग्लेशियर द्वारा क्षतिग्रस्त पार्श्व घाटियों में बड़ी झीलें शामिल हैं। ये झीलें सामान्यतः पीछे हटते ग्लेशियर के सामने रिसाव के माध्यम से अपना पानी बहा देती हैं। मोरेन स्थलाकृतिक अवसाद बनाता है जिसमें पिघला हुआ पानी आम तौर पर जमा होता है जिससे हिमनद झील का निर्माण होता है। जब यह झील जलरोधी होती है, तो पिघला हुआ पानी बेसिन में तब तक जमा होता रहेगा जब तक कि रिसाव या अतिप्रवाह झील के स्तर को सीमित नहीं कर देता।

अध्ययन क्षेत्र में हिमनद झीलों और जल निकायों का स्थान

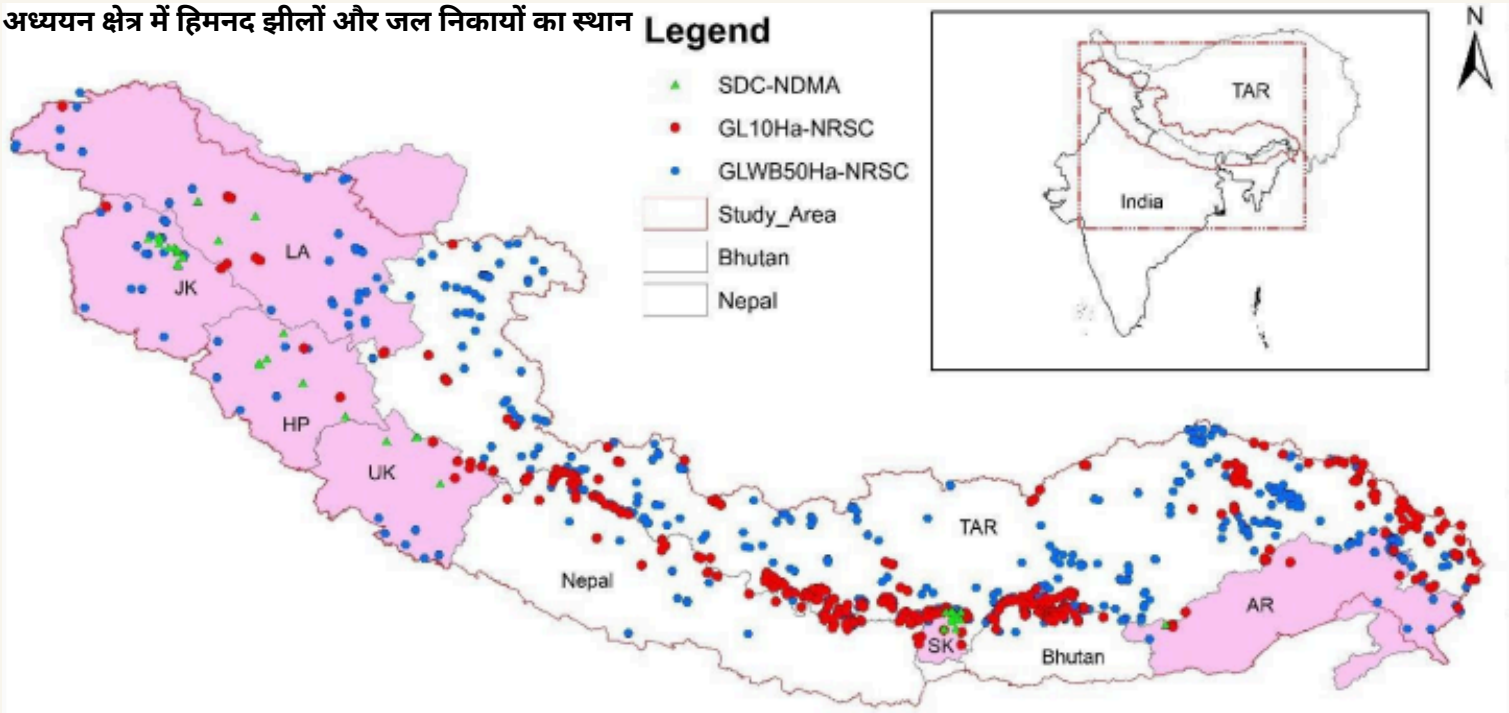

हिमनद झीलों और जल निकायों के जल प्रसार क्षेत्र में समग्र परिवर्तन

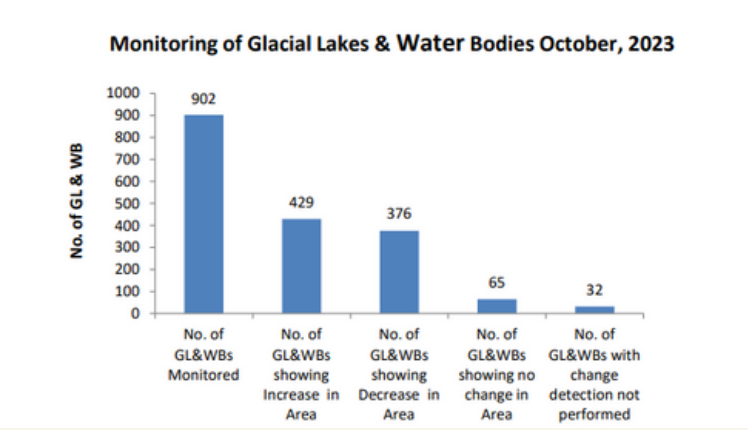

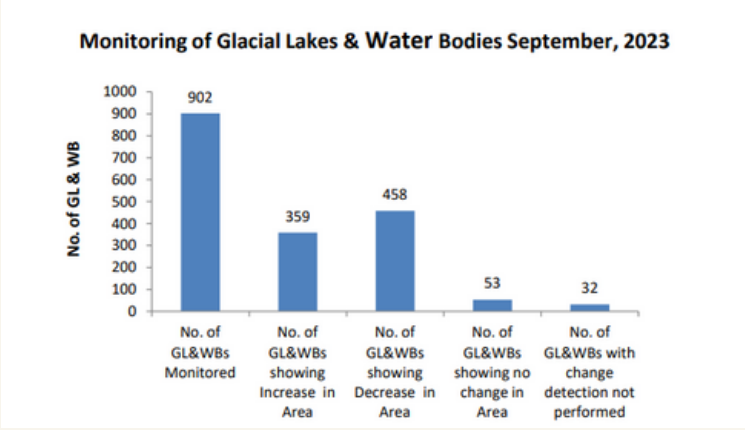

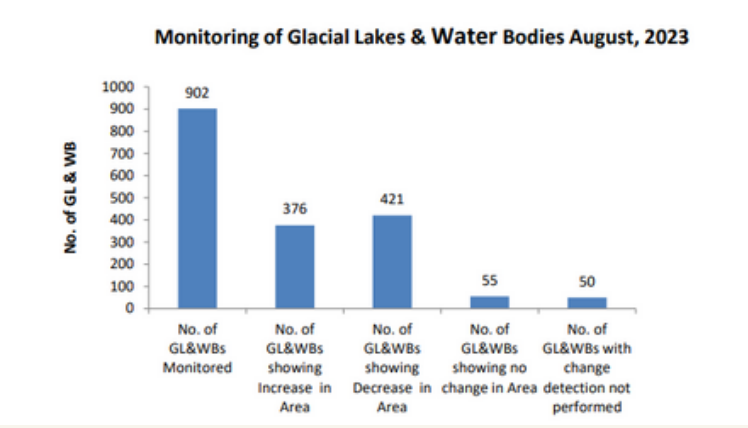

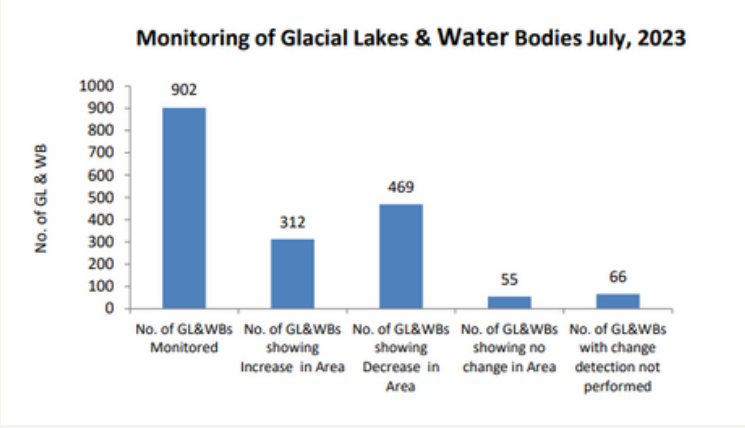

गैलरी

श्री सुबोध यादव, आईएएस, संयुक्त सचिव (प्रशासन, आईसी और जीडब्ल्यू), जलशक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, आरडी और जीआर विभाग ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित सीडब्ल्यूसी के जीडीएसक्यू स्थल भोमरागुड़ी (तेजपुर) का दौरा किया।

तकनीकी सलाहकार और समीक्षा समिति की बैठक (टीएआरसी) की 17वीं बैठक 09.11.2023 को सीडब्ल्यूसी के मुख्य अभियंता (एचएसओ) श्री मनोज तिवारी की अध्यक्षता में सात (7) नदी घाटियों में तलछट दर और तलछट परिवहन के आकलन के लिए भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग की परामर्श सेवाओं के काम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई थी।

सीडब्ल्यूईएस (ग्रुप-ए) जेटीएस अधिकारियों के लिए अनिवार्य कैडर प्रशिक्षण कार्यक्रम कल राष्ट्रीय जल अकादमी, केंद्रीय जल आयोग, पुणे में शुरू हुआ।

सीडब्ल्यूईएस (ग्रुप-ए) के लिए अनिवार्य कैडर प्रशिक्षण कार्यक्रम जेएजी अधिकारियों ने राष्ट्रीय जल अकादमी, केंद्रीय जल आयोग, पुणे में एक उद्घाटन समारोह के साथ शुरुआत की, जिसकी अध्यक्षता सीडब्ल्यूसी के पूर्व सदस्य और आईसीआईडी के पूर्व महासचिव डॉ. एम. गोपालकृष्णन ने की।

"IF THERE IS MAGIC ON THIS PLANET, IT IS CONTAINED IN WATER."

— LOREN EISELEY

केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- डॉ. बी.आर.के. पिल्लै, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री भूपिंद्र सिंह, निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री सुनीलकुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी—सी)- सदस्य
- श्री श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in